

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1780] No. 1780] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2008/अग्रहायण 28, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2008/AGRAHAYANA 28, 1930

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2943(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के यूनाइटेड लिब्नेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/55/2008-एन.ई.-III] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2008

S.O. 2943(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes 'The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal' consisting of Ms. Justice Reva Khetrapal, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/55/2008-NE.-III] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.